NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 14 Oct, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims**	खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 8 साल के निचले स्तर 1.54%पर पहुंच गई।
Page 06 **Syllabus : GS 1 : Social Issues /Prelims**	जन्मों की संख्या में गिरावट; मौतों में मामूली बढ़ोतरी: रिपोर्ट
Page 06 **Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims**	केंद्र के रूफटॉप सोलर लक्ष्यों को हासिल करना एक चुनौती बनी रहेगी: अध्ययन
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims**	आर्कटिक सील और पक्षी लुप्तप्राय प्रजातियों की नई 'लाल सूची' में: IUCN
Page 09 **Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims**	मोकिर, एगियोन और होविट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	भारत की संभावित विकास दर का अनुमान

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 **में तेजी से** 1.54% **तक कम हो गई, जो आठ वर्षों में सबसे कम स्तर को चिह्नित करती है. यह गिरावट खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी से प्रेरित थी, जिससे मुद्रास्फीति इस साल दूसरी बार आरबीआई के** 2% **के निचले कम्फर्ट बैंड से नीचे आ गई। डेटा मूल्य स्थिरता के एक चरण का संकेत देता है, जिससे संभावित मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीद बढ़ जाती है।**

मुख्य बिंदु

1. **ऐतिहासिक कम मुद्रास्फीति**
   - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) **द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति** सितंबर 2025 में गिरकर 1.54% **हो गई**, जो **जून** 2017 (1.46%) **के बाद से सबसे कम** है।
   - यह आंकड़ा **आरबीआई के** 2% **के कम सहिष्णुता बैंड से कम है**, जो महत्वपूर्ण मूल्य मॉडरेशन को दर्शाता है।
2. **सेक्टोरल ट्रेंड**
   - **खाद्य और पेय पदार्थ:** अगस्त में 0.05% और एक साल पहले 8.4% से 1.4% तक संकुचित।
   - **तेल और वसा:** 18.3% **पर ऊंचा रहा**, जो **लगातार** 11**वें महीने** दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को चिह्नित करता है।
   - **ईंधन और प्रकाश: अप्रैल (**एक महीने को छोड़कर) के बाद से गिरावट का रुझान जारी रखते हुए 1.98% तक गिर गया।
   - **कपड़े और जूते:** 2.28 प्रतिशत, जो अगस्त में 2.33 प्रतिशत था।
   - **आवास:** पिछले महीने 3.1% से बढ़कर 4% हो गया।
   - **पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ:** यह थोड़ा बढ़कर 2.7 **प्रतिशत** हो गया।
3. **विशेषज्ञ की राय**
   - **रजनी सिन्हा (केयरएज रेटिंग्स):** अनुकूल आधार और अच्छे मानसून **के कारण खाद्य मुद्रास्फीति नरमी बनी रहने की संभावना है**, हालांकि **देर से मानसून की वापसी और भारी बारिश** जोखिम पैदा कर सकती है।
   - **राजीव जुनेजा (पीएचडीसीसीआई):** खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट से **घरेलू क्रय शक्ति में सुधार हुआ है**।
4. **नीतिगत निहितार्थ**
   - आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) **ने** लगातार चौथी बार **मुद्रास्फीति के अनुमानों को संशोधित किया** है।
   - विश्लेषकों को उम्मीद है कि इससे **दिसंबर में नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश खुल** सकती है।

Retail inflation hits 8-year low of 1.54% in Sept.

Historic low

India's retail inflation slipped to 1.54% this month, the lowest since June 2017. The chart shows Y-o-Y inflation rate (in %)

SOURCE: MOSPI

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Retail inflation fell to a more than eight-year-low of 1.54% in September on falling food and fuel prices, official data showed on Monday. This is once again below the Reserve Bank of India's lower comfort bound of 2%.

Inflation, as measured by the Consumer Price Index released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, was last lower in June 2017, when it stood at 1.46%. Inflation had fallen below the RBI's lower comfort limit in July 2025, before rising marginally to 2.1% in August.

The food and beverages grouping saw a contraction of 1.4% in September, compared with a growth of 0.05% in August and 8.4% inflation in September last year.

Food inflation

"Looking ahead, food inflation is likely to stay benign supported by a favourable base and good monsoon," Rajani Sinha, chief economist at CareEdge Ratings, said.

"That said, risks remain from the late withdrawal of the monsoon and heavy rain in certain regions, which could risk crop damage."

In addition, Ms. Sinha said that persistently high double-digit inflation in edible oils warrants close monitoring, given weak sowing trends, import dependence, and elevated global edible oil prices.

Inflation in the oil and fats category stood at 18.3% in September, the 11th consecutive month of double-digit inflation in the sub-grouping.

Inflation in the fuel and light category came in at 1.98% in September, down from 2.3% in August. Save for one month, inflation in this category has been easing since April.

"The moderation in food and fuel prices has provided much-needed relief to households and improved purchasing power," Rajeev Juneja, president of the PHDCCI, said.

Inflation in the clothing and footwear category was 2.28% in September, marginally lower than the 2.33% seen in August 2025 and the 2.7% in September last year. This is the fifth consecutive month of slowing inflation in this category.

Inflation in the pan, tobacco and other intoxicants category, however, quickened to 2.7% in September from 2.5% in August.

Similarly, the housing sector also saw inflation quickening to 4% in September from 3.1% in the previous month.

Economists say that the low inflation figures, with the RBI's Monetary Policy Committee revising downwards its inflation forecast for the year for the fourth time in a row during its most recent monetary policy meeting, raises hopes of a rate cut in the next meeting in December.

दैनिक समाचार विश्लेषण

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक माप ।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क (2016)	आरबीआई का महंगाई लक्ष्य: 4% ± 2%। सितंबर का डेटा निचली सीमा से नीचे आता है।
रेपो दर और मौद्रिक संचरण	कम मुद्रास्फीति विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में कटौती का संकेत दे सकती है।
खाद्य मुद्रास्फीति की गतिशीलता	मानसून के रुझान, आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता से प्रेरित है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. **मूल्य नियंत्रण और ग्रामीण राहत**
   - खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट ने **घरेलू बोझ को कम कर** दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खपत मूल्य-संवेदनशील है।
   - खाद्य कीमतों में संकुचन **पिछले साल की** 8.4% **मुद्रास्फीति से तेज** उलटफेर का प्रतीक है, जो **आपूर्ति की स्थिति में सुधार का** संकेत देता है।
2. **नीति और विकास नेक्सस**
   - लगातार कम मुद्रास्फीति **आरबीआई को रेपो दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित** कर सकती है, जिससे निवेश और ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।
   - हालांकि, अल्ट्रा-लो मुद्रास्फीति **कमजोर मांग का संकेत दे सकती है**, जिसके लिए सावधानीपूर्वक नीति अंशांकन की आवश्यकता होती है।
3. **क्षेत्रीय असंतुलन**
   - समग्र नरमी के बावजूद, **तेल और वसा की मुद्रास्फीति** 18.3 **प्रतिशत है** जो आयात पर संरचनात्मक निर्भरता और वैश्विक मूल्य अस्थिरता को दर्शाती है।
   - **आवास और सेवाओं की मुद्रास्फीति में वृद्धि शहरी** क्षेत्रों में लागत के दबाव का सुझाव देती है।
4. **मानसून और खाद्य सुरक्षा**
   - एक **अच्छा मानसून खाद्य** मूल्य स्थिरता का समर्थन करता है, लेकिन असमान वर्षा और देर **से निकासी के जोखिम से** दालों और खराब होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो सकता है।

रणनीतिक निहितार्थ

- **आरबीआई के लिए:** दिसंबर की नीति में मौद्रिक सहजता **की गुंजाइश** ; हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति स्थिरता की निगरानी करनी चाहिए।
- **सरकार के लिए:** तत्काल मुद्रास्फीति जोखिम के बिना सार्वजनिक निवेश के माध्यम से **मांग को प्रोत्साहित** करने का अवसर।
- **परिवारों के लिए:** बढ़ी हुई **क्रय शक्ति** और उधार लेने की लागत में संभावित कमी।
- **व्यवसायों के लिए:** कम इनपुट लागत मुद्रास्फीति मार्जिन **को बढ़ा सकती है**, लेकिन कमजोर मांग विस्तार को सीमित कर सकती है।

आगे की चुनौतियाँ

- यह सुनिश्चित करना कि मुद्रास्फीति **अपस्फीतिकारी क्षेत्र में न पड़े**, जो विकास को कम कर सकती है।
- वैश्विक कमोडिटी की कीमतों (विशेष रूप से खाद्य तेलों और ऊर्जा) से आयातित **मुद्रास्फीति जोखिमों का** प्रबंधन।

- परिसंपत्ति के बुलबुले को रोकने के लिए **मौद्रिक विवेक** के साथ **विकास पुनरुद्धार को** संतुलित करना।
- आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के दौरान **मूल्य स्थिरता** बनाए रखना।

निष्कर्ष :

खुदरा मुद्रास्फीति में 8 साल के निचले स्तर पर तेज गिरावट भारत के लिए **व्यापक आर्थिक स्थिरता के एक दुर्लभ चरण को** रेखांकित करती है। कीमतों में ढील से घरों और नीति निर्माताओं को सांस लेने की जगह मिलती है, लेकिन स्थिति संभावित खाद्य आपूर्ति के झटके और वैश्विक कमोडिटी में उतार-चढ़ाव के खिलाफ सावधानीपूर्वक सतर्कता की मांग करती है। यदि इसे बनाए रखा जाता है, तो कम मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र एक **मापा मौद्रिक सहजता चक्र का मार्ग प्रशस्त कर सकता है**, जो FY2026 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. खुदरा मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा मापा जाता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड 4% ± 2% है।

3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 2% से नीचे की गिरावट का मतलब है कि यह आरबीआई के आराम क्षेत्र से बाहर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर : b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में हाल ही में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें। भारतीय रिज़र्व बैंक इस तरह के कम मुद्रास्फीति परिदृश्य में विकास पुनरुद्धार के साथ मूल्य स्थिरता को कैसे संतुलित कर सकता है? **(250 शब्द)**

Page 06: GS 1: Social Issues / Prelims

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) **पर आधारित और भारत के** रजिस्ट्रार जनरल (RGI) **द्वारा संकलित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट** (2023), भारत के लिए अद्यतन जनसांख्यिकीय रुझान प्रस्तुत करती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 **की तुलना में** दर्ज जन्मों की संख्या में मामूली गिरावट आई है, लेकिन **मौतों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है**। यह रिपोर्ट जनसंख्या की गतिशीलता, जन्म के समय लिंग अनुपात और राज्यों में संस्थागत पंजीकरण पैटर्न में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो अधिक स्थिर जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाती है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

Number of births declines; deaths rise slightly: report

The Vital Statistics of India, based on the Civil Registration System report for 2023, shows 86.6 lakh deaths were registered that year, recording a marginal increase from the 86.5 lakh in 2022

Vijaita Singh
NEW DELHI

India registered 2.52 crore births in 2023, around 2.32 lakh fewer than in 2022, the Vital Statistics of India based on the Civil Registration System (CRS) report for the year 2023 shows.

The report, compiled by the Registrar-General of India (RGI) and released on Monday, stated that 86.6 lakh deaths were registered in 2023, a marginal increase from 86.5 lakh deaths in 2022.

The report shows that there was no major spike in deaths in 2022 and 2023, despite the COVID-19 dashboard maintained by the Health Ministry showing that the total number of pandemic-induced deaths stood at 5,33,665 as on May 5.

However, there was a significant rise in deaths in 2021, the second-year of COVID-19 lockdown, which recorded an excess of 21 lakh deaths from the 2020 count.

There were 81.2 lakh deaths in 2020 and 102.2 lakh in 2021.

The report also said that Jharkhand recorded the lowest sex ratio at birth at 899, followed by Bihar at 900, Telangana at 906, Maharashtra at 909, Gujarat at 910, Haryana at 911 and Mizoram at 911. Since 2020, Bihar has been recording the lowest sex ratio, which is defined as the number of females born per 1,000 males.

Sex ratio count

The highest sex ratio was reported by Arunachal Pradesh at 1,085, followed by Nagaland at 1,007, Goa at 973, Ladakh and Tripura at 972, and Kerala at 967.

The share of institutional births in total registered births is 74.7% in 2023. However, the report did not include information from Sikkim. Overall registration of births for the year 2023 stood at 98.4%.

Statewise data

The report said that 11 States/Union Territories achieved more than 90% registration of births within the prescribed time limit of 21 days.

These States are Gujarat, Puducherry, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Haryana, Himachal Pradesh, Goa and Punjab. Five States – Odisha, Mizoram, Maharashtra, Chhattisgarh and Andhra Pradesh – reported 80-90% registration, while in 14 States – Assam, Delhi, Madhya Pradesh, Tripura, Telangana, Kerala, Karnataka, Bihar, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Jharkhand, West Bengal, Meghalaya and Uttar Pradesh – the registration stood at 50-80%.

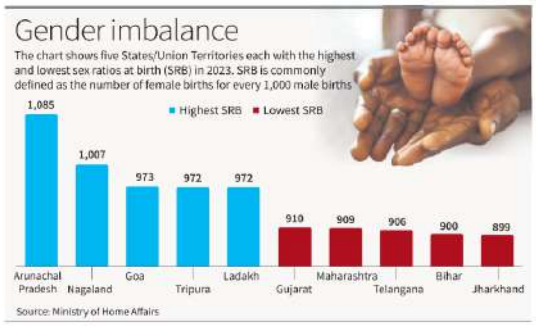

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

1. जन्म और मृत्यु डेटा

- **कुल जन्म** (2023): 2.52 करोड़ - 2022 (2.55 **करोड़**) **से** 2.32 लाख की गिरावट।
- **कुल मौतें** (2023): 86.6 लाख – 2022 **में** 86.5 **लाख से मामूली वृद्धि**।
- आधिकारिक तौर पर COVID-19 से 5.33 **लाख मौतों के बावजूद**, 2022-23 **में** कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई।
  - 2020: 81.2 लाख मौतें
  - 2021: 102.2 लाख (COVID पीक ईयर)
  - 2022: 86.5 लाख
  - 2023: 86.6 लाख

2. जन्म के समय लिंगानुपात (SRB)

- **सबसे कम एसआरबी:** झारखंड (899), बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911), मिजोरम (911)।
- **उच्चतम एसआरबी:** अरुणाचल प्रदेश (1085), नागालैंड (1007), गोवा (973), लद्दाख और त्रिपुरा (972), केरल (967)।

- बिहार में 2020 के बाद से सबसे कम एसआरबी **दर्ज किया गया है**, जो लैंगिक असमानता को जारी रखने का संकेत देता है।

3. संस्थागत और समय पर पंजीकरण

- **संस्थागत जन्म:** सभी पंजीकृत जन्मों का 74.7%।
- **समग्र पंजीकरण पूर्णता:** 98.4% (सिक्किम को छोड़कर)।
- **>90% समय पर पंजीकरण (21 दिनों के भीतर) वाले राज्य:** गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़, डीएनएच और डीडी, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब।
- **80-90% वाले राज्य:** ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश।
- **50-80% वाले राज्य:** असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, मेघालय, त्रिपुरा।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण	CRS 2023 डेटा **कम प्रजनन क्षमता और जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बदलाव को दर्शाता है**।
लिंग मुद्दे और लिंग अनुपात	उत्तरी राज्यों में लगातार कम एसआरबी समाज में **चल रहे लिंग पूर्वाग्रह** को दर्शाता है ।
लोक स्वास्थ्य प्रशासन	पंजीकरण दक्षता और संस्थागत प्रसव **में सुधार** मजबूत शासन को प्रदर्शित करता है।
जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	सार्वभौमिक महत्वपूर्ण पंजीकरण **और** मातृ-शिशु स्वास्थ्य कवरेज **के नीतिगत उद्देश्यों का समर्थन करता है**।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. जनसंख्या स्थिरीकरण के संकेत

- जन्म पंजीकरण संख्या में गिरावट प्रजनन **दर में गिरावट और** जनसंख्या स्थिरीकरण **की दिशा में एक आंदोलन** का संकेत देती है, खासकर शहरी और दक्षिणी भारत में।
- परिवार नियोजन और सामाजिक-आर्थिक विकास **की सफलता का** संकेत देता है।

2. लैंगिक असमानता और सामाजिक चुनौतियाँ

- जन्म के समय **लगातार कम लिंगानुपात पुरुष** बच्चों के लिए सांस्कृतिक प्राथमिकता, **कन्या भ्रूण हत्या की चिंताओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में लैंगिक असमानता** को उजागर करता है।
- अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्य **बेहतर सामाजिक समानता मॉडल प्रदर्शित करते हैं**।

3. कोविड के बाद मृत्यु दर स्थिरीकरण

- डेटा से पता चलता है कि 2021 **की मृत्यु दर में वृद्धि** सामान्य हो गई है, जो **स्वास्थ्य प्रणाली की वसूली** और महामारी से बाहर निकलने के चरण को दर्शाती है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी उपकरण के **रूप में सीआरएस की विश्वसनीयता को मजबूत करता** है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

4. संस्थागत प्रसव और प्रशासनिक दक्षता

- 74.7% संस्थागत जन्म के साथ, भारत मातृ **और नवजात स्वास्थ्य देखभाल में सुधार दिखाता है**।
- हालांकि, **कई राज्यों में विलंबित** या अधूरे पंजीकरण शासन **अंतराल** और डिजिटल विभाजन के मुद्दों को उजागर करते हैं।

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- **नीति निर्माण**: जनसंख्या नीति, कल्याण योजनाओं और राजकोषीय नियोजन **के लिए महत्वपूर्ण**।
- **लैंगिक न्याय**: डेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ **और संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों** का मार्गदर्शन कर सकता है।
- **अनुसंधान और शिक्षा**: जनसांख्यिकीय अध्ययन, **सार्वजनिक स्वास्थ्य** और **यूपीएससी जीएस पेपर** । **और** ।। के लिए उपयोगी डेटासेट।
- **डिजिटल गवर्नेंस**: वास्तविक समय डिजिटल नागरिक पंजीकरण **प्रणाली** को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- पंजीकरण दक्षता और डेटा सटीकता में क्षेत्रीय असमानताएं।
- सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद लैंगिक असंतुलन जारी है।
- व्यापक जनसांख्यिकीय विश्लेषण के लिए **सीआरएस**, **एनएफएचएस और जनगणना डेटाबेस के एकीकरण** की आवश्यकता है।
- ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता अंतराल और प्रशासनिक देरी।

निष्कर्ष :

भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2023 भारत के एक परिपक्व जनसांख्यिकीय चरण **में प्रवेश को रेखांकित करते हैं**, जो घटती जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर से चिह्नित है। जबकि देश **जनसंख्या स्थिरीकरण के करीब पहुंच गया है**, पंजीकरण **में लैंगिक असंतुलन** और **क्षेत्रीय विसंगतियां** चिंता के क्षेत्र बनी हुई हैं। **साक्ष्य-आधारित शासन और** स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या डेटा प्रबंधन पर एसडीजी लक्ष्यों **को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक**, **समय पर और पारदर्शी नागरिक पंजीकरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा**।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2023 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया?

(a) केरल

(b) नागालैंड

(c) अरुणाचल प्रदेश

(d) त्रिपुरा

उत्तर: (c)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत की घटती जन्म दर जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रगति को दर्शाती है, लेकिन नई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां भी पैदा करती है। भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी 2023 के हालिया जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संदर्भ में चर्चा करें।

Page 06 : GS 3 : Environment / Prelims

इंस्टीट्यूट **फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस** (IEEFA) और JMK **रिसर्च एंड एनालिटिक्स** ने संयुक्त रूप से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGY) **की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है**, जिसे भारत सरकार द्वारा आवासीय रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 2024 की शुरुआत से एप्लीकेशन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, अध्ययन में पाया गया है कि **जुलाई** 2025 तक सरकार के महत्वाकांक्षी 1 **करोड़ रूफटॉप लक्ष्य का** केवल 13.1% **प्राप्त किया गया है**, जिससे FY2027 **लक्ष्य** तेजी से चुनौतीपूर्ण हो जाता है. रिपोर्ट में प्रक्रियात्मक अड़चनों, उच्च घरेलू घटक लागत और विलंबित अनुमोदन को योजना की सफलता में प्रमुख बाधाओं के रूप में उजागर किया गया है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

Achieving Centre's rooftop solar targets to remain a challenge: study

Jacob Koshy
NEW DELHI

Despite a near four-fold increase in applications between March 2024 and July 2025, only 13.1% of the targeted 1 crore solar rooftop installations, under the PM Surya Ghar Yojana (PMSGY), has been achieved, and just 14.1% of the allocated ₹65,700 crore in subsidies released till July 2025, a report said.

"In this scenario, the FY2027 target [of 1 crore installations] continues to be viewed as a considerable challenge," said the report on the performance of the scheme, jointly published by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) and JMK Research and Analytics on Tuesday.

Reasons included tardy approval processes, which could stretch anywhere from 45 to 120 days, stemming largely from "meter shortages, lack of coordination between consumers, installers, and DISCOMs, and procedural inefficiencies at the utility level," it noted.

The scheme has facilitated the installation of 4,946 MW of rooftop solar capacity till July 2025 across States and Union Territories.

The PMSGY is a Centre-led endeavour to encourage more homes to install rooftop solar connections. The government provides capital upfront via loans.

As of July 2025, the period until which the report tracked progress, the PMSGY had received 57.9 lakh applications for residential rooftop solar installations. The scheme has facilitated the installation of 4,946 MW of rooftop solar capacity till July 2025 across various States and Union Territories, indicating "robust on-ground execution", the report said. Subsidy disbursements have crossed ₹9,281 crore ($1.05 billion), benefiting over 16 lakh households. As of July 2025, the 4.9 GW of installations added under the PMSGY accounted for approximately 44.5% of the country's total residential rooftop capacity.

The PM solar scheme only incentivises solar installations, whose component parts are entirely manufactured in India. Called "DCR-compliant modules", they are on average costlier by ₹12/watt over imported variants. "These higher prices are making larger residential installations less economically attractive," the report said.

"Establishing clear, time-bound rooftop solar capacity targets at the State level is essential for creating a coherent vision," said Vibhuti Garg, Director, IEEFA-South Asia, and a contributing author, in a statement.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

1. प्रगति और प्रदर्शन

- **प्राप्त आवेदन**: 57.9 लाख (जुलाई 2025 तक) - **मार्च** 4× **से लगभग** 2024 की वृद्धि।
- **प्राप्त किए गए इंस्टॉलेशन**: लक्ष्य का केवल 13.1% (यानी, लगभग 13 लाख इंस्टॉलेशन)।
- **स्थापित क्षमता**: **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में** 4,946 **मेगावाट** (4.9 **गीगावॉट**) रूफटॉप सोलर।
- **कुल आवासीय छत क्षमता में हिस्सेदारी**: राष्ट्रीय कुल का **लगभग** 44.5%।

दैनिक समाचार विश्लेषण

2. वित्तीय स्थिति

- **कुल योजना परिव्यय**: ₹65,700 करोड़
- **वितरित सब्सिडी** (**जुलाई** 2025 **तक**): ₹9,281 करोड़ (कुल का ~14.1%)।
- **लाभार्थी परिवार**: 16 लाख से **अधिक**।

3. कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- **अनुमोदन में देरी: प्रक्रियाओं में 45-120 दिन लगते हैं:**
  - मीटर की कमी,
  - उपभोक्ताओं, इंस्टॉलरों और डिस्कॉम के बीच समन्वय की कमी,
  - उपयोगिता स्तर पर प्रक्रियात्मक अक्षमताएं।
- **लागत की कमी:**
  - यह योजना DCR-अनुरूप मॉड्यूल (**पूरी तरह से भारतीय निर्मित**) के उपयोग को अनिवार्य करती है।
  - घरेलू पैनलों की कीमत आयातित पैनलों **की तुलना में** ₹12/W **अधिक है**, जिससे बड़े इंस्टॉलेशन के लिए आर्थिक आकर्षण कम हो जाता है.

4. सिफारिशें

- जवाबदेही बढ़ाने के लिए **स्पष्ट**, **समयबद्ध राज्य-स्तरीय लक्ष्य** स्थापित करें।
- केंद्रीय एजेंसियों, राज्य डिस्कॉम और निजी विक्रेताओं के बीच **समन्वय तंत्र** में सुधार करना।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और सौर नीति	पीएमएसजीवाई 2030 तक भारत के 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य **को प्राप्त करने में योगदान देता है**।
विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियाँ	रूफटॉप सोलर **घरेलू स्तर पर ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देता** है और ग्रिड दबाव को कम करता है।
घरेलू विनिर्माण (DCR **नीति**)	सौर मॉड्यूल के लिए **आत्मनिर्भर भारत** और **पीएलआई योजना** के अनुरूप
जलवायु प्रतिबद्धताएं (**पेरिस समझौता और** COP28 **लक्ष्य**)	भारत के नेट जीरो 2070 **रोडमैप** के लिए महत्वपूर्ण।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. कार्यान्वयन अंतराल और नौकरशाही देरी

- डिस्कॉम में धीमी मंजूरी और समन्वय विफलता **विकेंद्रीकृत नीति निष्पादन में प्रशासनिक** अक्षमता को उजागर करती है।
- लंबी प्रक्रियात्मक समयसीमा घरेलू भागीदारी को हतोत्साहित करती है और सब्सिडी प्रवाह में देरी करती है।

2. घरेलू विनिर्माण बनाम सामर्थ्य

- जबकि डीसीआर अनुपालन **घरेलू उद्योग और ऊर्जा संप्रभुता को मजबूत करता है**, यह परियोजना लागत बढ़ाता है।
- लागत प्रतिस्पर्धात्मकता **के साथ** आत्मनिर्भरता **को संतुलित करना** एक प्रमुख नीतिगत दुविधा बनी हुई है।

3. वित्तपोषण और उपभोक्ता जागरूकता

- सब्सिडी **जारी करने में देरी और जटिल ऋण प्रक्रियाएं** मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के बीच गोद लेने को प्रतिबंधित करती हैं।
- तकनीकी मार्गदर्शन और स्थापना के बाद समर्थन की कमी भी भागीदारी में बाधा डालती है।

4. ऊर्जा परिवर्तन में भूमिका

- रूफटॉप सोलर में भारत के **शहरी ऊर्जा परिदृश्य को बदलने**, ट्रांसमिशन नुकसान और जीवाश्म निर्भरता को कम करने की क्षमता है।
- हालांकि, वर्तमान प्रगति इंगित करती है कि **वित्त वर्ष** 2027 **तक** 1 **करोड़ इंस्टॉलेशन** प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन और अंतर-एजेंसी तालमेल की आवश्यकता है.

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- **नीति निर्माताओं के लिए**: नवीकरणीय परिनियोजन में **राज्य-वार सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण** और **सुव्यवस्थित नियामक ढांचे** के मामले को मजबूत करता है।
- **उद्योग के लिए**: डीसीआर मॉड्यूल को किफायती बनाने के लिए **घरेलू नवाचार** और **पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं** की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **अनुसंधान और शिक्षा के लिए**: सार्वजनिक-निजी ऊर्जा संक्रमण चुनौतियों **में अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है** - यूपीएससी जीएस पेपर III (ऊर्जा, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा) **के लिए प्रासंगिक**।
- **शासन के लिए**: **यह** रेखांकित करता है कि **भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में** कार्यान्वयन क्षमता **नीतिगत महत्वाकांक्षा के** रूप में कैसे महत्वपूर्ण है।

आगे की चुनौतियाँ

- प्रक्रियात्मक देरी और डिस्कॉम, विक्रेताओं और परिवारों के बीच कमजोर समन्वय।
- उच्च घरेलू मॉड्यूल लागत लागत-प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
- सब्सिडी वितरण में डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता का अभाव।
- असमान राज्य-स्तरीय भागीदारी - कुछ लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
- सतत अपनाने के लिए **कौशल विकास और उपभोक्ता जागरूकता** की आवश्यकता।

निष्कर्ष :

आईईईएफए-जेएमके अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि पीएम **सूर्य घर योजना ने** मजबूत रुचि और अनुप्रयोग वृद्धि को गति दी है, लेकिन इसकी **निष्पादन दक्षता** प्रमुख बाधा बनी हुई है। **रूफटॉप लक्ष्य का केवल** 13% **प्राप्त करने** और 14% **सब्सिडी वितरित करने के साथ**, FY2027 लक्ष्य **को प्राप्त करने के लिए** तत्काल पॉलिसी फाइन-ट्यूनिंग, तेज़ अप्रूवल और बेहतर लागत युक्तिकरण की आवश्यकता होती है. यह रिपोर्ट एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सौर **ऊर्जा से संचालित भविष्य में भारत का परिवर्तन न केवल** महत्वाकांक्षी लक्ष्यों **पर निर्भर करेगा**, **बल्कि** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समावेशी और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए **संस्थागत चपलता**, **स्थानीय भागीदारी और वित्तीय नवाचार पर** भी निर्भर करेगा।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: डीसीआर-अनुरूप सौर मॉड्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इनका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाना चाहिए।

2. वे आयातित सौर मॉड्यूल की तुलना में सस्ते हैं।

3. पीएम सूर्य घर योजना के तहत इन्हें अनिवार्य किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) 1 और 2

b) 1 और 3

c) 2 और 3

d) उपरोक्त सभी

उत्तर : b)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत की पीएम सूर्य घर योजना के रूफटॉप सौर लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की गंभीर रूप से जांच करें। घरेलू विनिर्माण और सामर्थ्य को संतुलित करते हुए अपनाने में तेजी लाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। **(250 शब्द)**

Page : 07: GS 3 : Environment/ Prelims

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) **ने** विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 **में** संकटग्रस्त प्रजातियों की **अपनी अद्यतन** लाल सूची जारी की। रिपोर्ट **आर्कटिक सील**, **पक्षी प्रजातियों और अन्य वन्यजीवों** के सामने आने वाले बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डालती है, जो मुख्य रूप से **जलवायु परिवर्तन**, **निवास स्थान के नुकसान और मानव गतिविधि** से प्रेरित हैं। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक मूल्यांकन है, जिसमें 172,620 **प्रजातियां** शामिल हैं, जिनमें से 48,646 **के विलुप्त होने का खतरा है**। रिपोर्ट तत्काल **प्रकृति-आधारित रिकवरी**, **जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है**।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

1. आर्कटिक सील की स्थिति

- **हुड वाली सील**: कमजोर से लुप्तप्राय में अपग्रेड किया गया।
- **दाढ़ी और वीणा सील**: खतरे के निकट के **रूप में वर्गीकृत**।
- प्रमुख खतरे: **ग्लोबल वार्मिंग**, **समुद्री यातायात**, **तेल निष्कर्षण**, **औद्योगिक मछली पकड़ना**, **शिकार**।
- **आर्कटिक वार्मिंग**: वैश्विक औसत की तुलना में 4× तेजी से **हो रहा है**, समुद्री बर्फ को काफी कम कर रहा है, जो बर्फ पर निर्भर सील के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- **पारिस्थितिक भूमिका**: कीस्टोन प्रजातियां, आर्कटिक खाद्य जाले के लिए केंद्रीय, पोषक तत्व पुनर्चक्रण, और अन्य जानवरों के लिए शिकार।

2. पक्षी प्रजातियों की स्थिति

- 61% **पक्षी प्रजातियों** में अब घटती **आबादी** है (2016 में 44% से)।
- 1,256 **पक्षी प्रजातियां** (**मूल्यांकन किए गए** 11,185 **का** 11.5%) **विश्व** स्तर पर खतरे में हैं।
- प्रमुख खतरे: वनों की कटाई **से निवास** स्थान का नुकसान, **कृषि विस्तार**, विशेष रूप से **मेडागास्कर**, **पश्चिम अफ्रीका**, **मध्य अमेरिका में**।
- सकारात्मक विकास: हरे कछुओं **की तरह संरक्षण की सफलता की कहानियां**, 1970 के दशक के बाद से जनसंख्या में 28% की वृद्धि हुई।

3. वैश्विक प्रजाति कवरेज

- मूल्यांकन की गई कुल प्रजातियां: 172,620
- संकटग्रस्त प्रजातियां: 48,646
- पक्षियों, स्तनधारियों, समुद्री प्रजातियों और सरीसृपों **पर वैश्विक डेटा को एकीकृत करते हुए**, हजारों विशेषज्ञों **द्वारा नौ साल के काम पर ध्यान केंद्रित किया गया**।

4. मानव और जलवायु प्रभाव

The IUCN World Congress will drive action on nature-based recovery, climate change, and biodiversity. AFP

Arctic seals, birds in new 'red list' of endangered species: IUCN

Agence France Presse

Arctic seals and birds are coming under increasing threat, mainly due to climate change and human activity, according to an updated list of endangered species released Friday by the world's top conservation body.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) said habitat loss driven by logging and agricultural expansion is a threat to birds. At the same time, seals were at risk mostly due to global warming and human activities, including maritime traffic.

The IUCN said it was changing the status of the hooded seal from vulnerable to endangered while bearded and harp seals are now classified as near threatened.

"This timely global update highlights the ever increasing impact human activity is having on nature and the climate and the devastating effects this has," its director general Grethel Aguilar told reporters at its World Conservation Congress in Abu Dhabi.

The IUCN red list now includes "172,620 species of which 48,646 are threatened with extinction," it said in a statement.

Global warming is destroying the natural habitat of animals including seals that live in the cold parts of the world. Maritime traffic, mining and oil extraction, industrial fishing and hunting are among other risks to the species.

"Global warming is occurring four times faster in the Arctic than in other regions, which is drastically reducing the extent and duration of sea ice cover," the IUCN said.

"Ice-dependent seals are a key food source for other animals," it added.

They "play a central role in the food web, consuming fish and invertebrates and recycling nutrients" and are one of the "keystone species" of their ecosystem.

Kit Kovacs, a scientist at the Norwegian Polar Institute, raised the alarm about the Svalbard archipelago, halfway between Norway and the North Pole.

Habitat loss is a threat to birds. At the same time, seals were at risk mostly due to global warming and human activities

"When I lived on the archipelago, just a couple of decades ago, we had five months of sea ice cover in areas that are now winter ice-free. It is really hard to express just how rapidly the Arctic is changing," she said.

The IUCN said its red list of birds is the fruit of nine years of work by "thousands of experts".

"Overall, 61% of bird species have declining populations – an estimate that has increased from 44 percent in 2016," the IUCN said.

It studied thousands of bird species worldwide and found that "1,256 (or 11.5%) of the 11,185 species assessed are globally threatened".

This year's update focused on regions where the destruction of tropical forest poses a growing threat to birds. In Madagascar, 14 species were newly classified as near threatened and three others were labelled vulnerable. In West Africa, five more bird species were found to be near threatened in addition to one more in Central America.

The report also mentioned a positive development. The green turtle is no longer endangered, it said, citing "decades of sustained conservation action" that saw its population recover by 28% since the 1970s.

Nicolas Pilcher, the Executive Director of the Marine Research Foundation, said this success should spur action not complacency.

"Just because we have reached this great step in conservation isn't a reason to sit back and then become complacent," he said.

- समुद्री यातायात, खनन और तेल निष्कर्षण आर्कटिक सील को खतरे में डालते हैं।
- उष्णकटिबंधीय वन विनाश पक्षी प्रजातियों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है।
- आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र में तेजी से परिवर्तन, जैसे कि स्वालबार्ड द्वीपसमूह, **सिकुड़ती बर्फ की अवधि का संकेत देता** है, जिससे प्रजातियों का अस्तित्व प्रभावित होता है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
जैव विविधता और आईयूसीएन रेड लिस्ट	अद्यतन सूची विश्व स्तर पर विलुप्त होने के जोखिम और प्रजातियों के संरक्षण की प्राथमिकताओं को ट्रैक करती है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव	आर्कटिक बर्फ के नुकसान और बढ़ते वैश्विक तापमान से ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र और प्रवासी प्रजातियों को खतरा है।
पर्यावास का नुकसान और वनों की कटाई	उष्णकटिबंधीय वन विनाश सीधे पक्षियों की आबादी में गिरावट में योगदान देता है।
इकोसिस्टम सेवाएं और कीस्टोन प्रजातियां	बर्फ पर निर्भर सील और कुछ पक्षी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. प्राथमिक चालक के रूप में जलवायु परिवर्तन

- आर्कटिक प्रजातियां तेजी से गर्म होने की दर **और बर्फ के आवासों के सिकुड़ने** के कारण असमान रूप से प्रभावित होती हैं।
- जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधि और जैव विविधता के नुकसान के परस्पर संबंध **पर प्रकाश डालता है**।

2. मानव गतिविधि और आवास क्षरण

- लॉगिंग, कृषि विस्तार, औद्योगिक मछली पकड़ना और समुद्री गतिविधियाँ **स्थलीय और समुद्री दोनों प्रजातियों के लिए** महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं।
- स्थायी भूमि उपयोग और समुद्री प्रबंधन **की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है**।

3. संरक्षण सफलताएँ और सबक

- हरे कछुए की वसूली (1970 के दशक के बाद से 28% वृद्धि) से पता चलता है कि **निरंतर संरक्षण हस्तक्षेप गिरावट को** उलट सकते हैं।
- सफलता की कहानियाँ **नीति प्रभावशीलता, सामुदायिक जुड़ाव और दीर्घकालिक निगरानी पर जोर देती हैं**।

4. जैव विविधता निगरानी और वैश्विक कार्रवाई

- IUCN रेड लिस्ट वैश्विक **संरक्षण नीतियों के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है**, जिसमें CITES, CBD **और राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ शामिल हैं**।
- जलवायु-लचीली संरक्षण योजना **के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता** है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- **नीति निर्माताओं के लिए:** राष्ट्रीय और वैश्विक जैव विविधता नीतियों को सूचित करना; **वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना**।
- **पर्यावरण प्रबंधन के लिए:** बर्फ पर निर्भर, कीस्टोन और संकटग्रस्त प्रजातियों **के संरक्षण को प्राथमिकता दें**; संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को विनियमित करें।
- **शिक्षा और अनुसंधान के लिए:** पारिस्थितिकी, जलवायु विज्ञान और पर्यावरण कानून अध्ययन **के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है**।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए**: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) **और** एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) **लक्ष्यों का** समर्थन करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- तेजी से आर्कटिक वार्मिंग और समुद्री बर्फ का नुकसान **संरक्षण प्रयासों से आगे निकल सकता है**।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में **वनों की कटाई और कृषि** के कारण निवास स्थान का नुकसान जारी है।
- वैश्विक और राष्ट्रीय संरक्षण उपायों का प्रवर्तन **असमान बना हुआ है**।
- संरक्षण की सफलता की कहानियों को बढ़ाने के लिए **धन**, **प्रौद्योगिकी और सामुदायिक जुड़ाव** की आवश्यकता है।
- लाल सूची की निगरानी और अद्यतन करने के लिए **सभी देशों में** निरंतर वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष :

IUCN **रेड लिस्ट** 2025 **अपडेट** जलवायु परिवर्तन और मानव-प्रेरित आवास हानि के कारण आर्कटिक सील, पक्षियों और अन्य प्रजातियों की बढ़ती भेद्यता **को रेखांकित करता है** । जबकि कुछ सफलता की कहानियाँ जैसे हरे कछुए निरंतर संरक्षण कार्रवाई के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, समग्र प्रवृत्ति घटती **आबादी और विलुप्त होने के जोखिम को बढ़ाती है**। यह रिपोर्ट **कमजोर प्रजातियों की रक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए** वैश्विक जैव विविधता शासन, प्रकृति-आधारित पुनर्प्राप्ति रणनीतियों और जलवायु शमन की तात्कालिकता को पुष्ट करती है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न : IUCN रेड लिस्ट 2025 अपडेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हुड वाली सील को लुप्तप्राय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. दाढ़ी और वीणा सील को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. 61% पक्षी प्रजातियों में अब घटती जनसंख्या के रुझान दिखाई दे रहे हैं।
4. हरे कछुए अभी भी लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न : आईयूसीएन रेड लिस्ट 2025 रिपोर्ट में रेखांकित आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के लिए प्रमुख खतरों पर चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता के नुकसान को कैसे बढ़ाता है? **(150 शब्द)**

Page 12 : GS 3 : Indian Economy/ Prelims

आर्थिक विज्ञान में 2025 **का नोबेल पुरस्कार** जोएल मोकिर, फिलिप एघियन और पीटर होविट **को नवाचार-संचालित आर्थिक विकास** पर उनके मौलिक कार्य के लिए **प्रदान किया गया**। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका शोध बताता है कि कैसे निरंतर आर्थिक विकास तकनीकी नवाचार पर निर्भर करता है, और कैसे "रचनात्मक विनाश" पुराने उत्पादों को नए और बेहतर लोगों के साथ निरंतर प्रतिस्थापन सुनिश्चित करता है। 11 **मिलियन स्वीडिश क्रोनर** ($1.2 **मिलियन**) मूल्य का यह पुरस्कार, दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के चालक के रूप में नवाचार **के महत्व को रेखांकित करता है**।

पुरस्कार की मुख्य विशेषताएं

1. पुरस्कार विजेता और योगदान

- **जोएल मोकिर (नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूएसए):**
  - तकनीकी नवाचारों के **माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक कारकों की पहचान करने के लिए** ऐतिहासिक विश्लेषण **का उपयोग किया**।
  - पुरस्कार का आधा हिस्सा **दिया गया**।
- **फिलिप एघिओन (कॉलेज डी फ्रांस और इनसीड, पेरिस; एलएसई, यूके) और पीटर हॉविट (ब्राउन यूनिवर्सिटी, यूएसए)**:
  - रचनात्मक विनाश का गणितीय मॉडल **विकसित किया**, यह दिखाते हुए कि कैसे नए नवाचार एक अंतहीन चक्र में पुराने उत्पादों को बदल देते हैं।
  - पुरस्कार का दूसरा आधा हिस्सा **साझा किया**।

2. उनके काम का महत्व

- इस धारणा को चुनौती देता है कि आर्थिक विकास स्वचालित है; **विकास की तुलना में ठहराव ऐतिहासिक रूप से अधिक आम रहा है**।
- नीति और उद्यमिता के लिए रूपरेखा **प्रदान करता है**, दीर्घकालिक **विकास के लिए नवाचार** आधारित विकास पर जोर देता है।

3. पुरस्कार संदर्भ

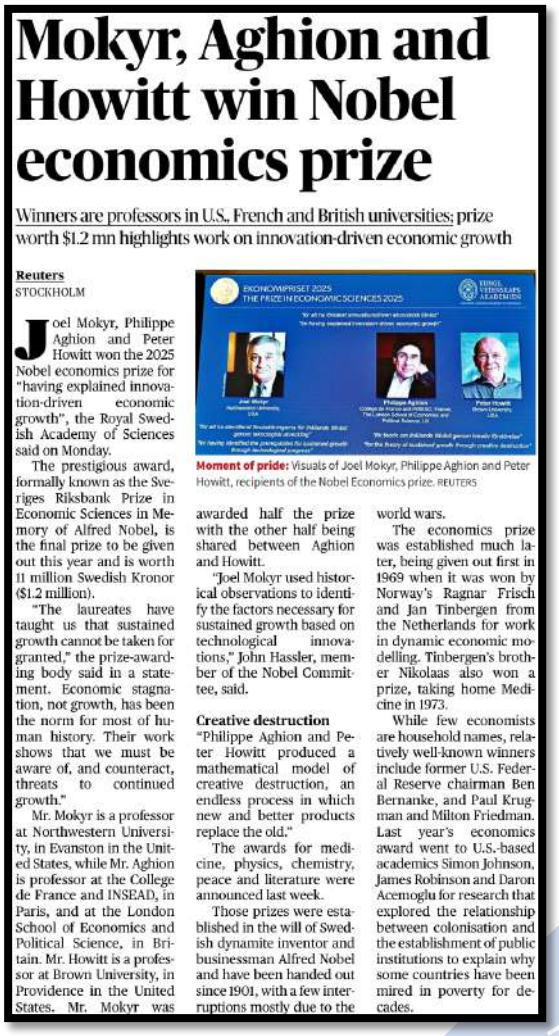

Mokyr, Aghion and Howitt win Nobel economics prize

Winners are professors in U.S., French and British universities; prize worth $1.2 mn highlights work on innovation-driven economic growth

Reuters
STOCKHOLM

Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt won the 2025 Nobel economics prize for "having explained innovation-driven economic growth", the Royal Swedish Academy of Sciences said on Monday.

The prestigious award, formally known as the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, is the final prize to be given out this year and is worth 11 million Swedish Kronor ($1.2 million).

"The laureates have taught us that sustained growth cannot be taken for granted," the prize-awarding body said in a statement. Economic stagnation, not growth, has been the norm for most of human history. Their work shows that we must be aware of, and counteract, threats to continued growth."

Mr. Mokyr is a professor at Northwestern University, in Evanston in the United States, while Mr. Aghion is professor at the College de France and INSEAD, in Paris, and at the London School of Economics and Political Science, in Britain. Mr. Howitt is a professor at Brown University, in Providence in the United States. Mr. Mokyr was awarded half the prize with the other half being shared between Aghion and Howitt.

"Joel Mokyr used historical observations to identify the factors necessary for sustained growth based on technological innovations," John Hassler, member of the Nobel Committee, said.

Creative destruction

"Philippe Aghion and Peter Howitt produced a mathematical model of creative destruction, an endless process in which new and better products replace the old."

The awards for medicine, physics, chemistry, peace and literature were announced last week.

Those prizes were established in the will of Swedish dynamite inventor and businessman Alfred Nobel and have been handed out since 1901, with a few interruptions mostly due to the world wars.

The economics prize was established much later, being given out first in 1969 when it was won by Norway's Ragnar Frisch and Jan Tinbergen from the Netherlands for work in dynamic economic modelling. Tinbergen's brother Nikolaas also won a prize, taking home Medicine in 1973.

While few economists are household names, relatively well-known winners include former U.S. Federal Reserve chairman Ben Bernanke, and Paul Krugman and Milton Friedman. Last year's economics award went to U.S.-based academics Simon Johnson, James Robinson and Daron Acemoglu for research that explored the relationship between colonisation and the establishment of public institutions to explain why some countries have been mired in poverty for decades.

Moment of pride: Visuals of Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt, recipients of the Nobel Economics prize. REUTERS

- नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था; पहली बार गतिशील आर्थिक मॉडलिंग **के लिए रग्नार फ्रिश और जान टिनबर्गेन को सम्मानित किया** गया।
- पिछले उल्लेखनीय विजेताओं में बेन **बर्नानके**, **पॉल क्रुगमैन**, **मिल्टन फ्रीडमैन और पिछले साल के साइमन जॉनसन**, **जेम्स रॉबिन्सन और डारोन एसेमोग्लू** (उपनिवेशीकरण और संस्थानों पर शोध के लिए) शामिल हैं।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
नवाचार और आर्थिक विकास	इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार निरंतर विकास को बढ़ावा देते हैं, जो आधुनिक ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक है
रचनात्मक विनाश (Schumpeterian **मॉडल**)	नई प्रौद्योगिकियों द्वारा औद्योगिक विकास और विरासत उद्योगों के विघटन की व्याख्या करता है।
ऐतिहासिक आर्थिक विश्लेषण	मोकिर का दृष्टिकोण **ऐतिहासिक संदर्भ को आधुनिक विकास नीति से जोड़ता है**।
नीति और संस्थागत अर्थशास्त्र	सरकारों और संस्थानों को अनुसंधान एवं विकास, उद्यमिता और नवाचार इकोसिस्टम **को** प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को डिजाइन करने के बारे में सूचित किया

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. विकास इंजन के रूप में नवाचार

- पुरस्कार विजेता प्रदर्शित करते हैं कि **तकनीकी नवाचार** दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्रीय है।
- विकास को बनाए रखने के लिए तंत्र के रूप में **अनुसंधान एवं विकास**, **शिक्षा और स्टार्ट-अप में निवेश को** प्रोत्साहित किया

2. रचनात्मक विनाश

- बाजार स्वाभाविक रूप से पुराने उत्पादों के विस्थापन के माध्यम से नए, **ड्राइविंग दक्षता और उत्पादकता** के माध्यम से विकसित होते हैं।
- आवश्यक नीतिगत संतुलन **पर प्रकाश डालता है**: औद्योगिक बदलावों के कारण सामाजिक और रोजगार व्यवधानों का प्रबंधन करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करना।

3. आधुनिक नीति के लिए ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि

- मोकिर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि **ऐसे समाज जो जोखिम ठहराव को नया करने में विफल रहते** हैं, संस्थागत और शैक्षिक बुनियादी ढांचे **के महत्व को मजबूत करते हैं**।

4. वैश्विक प्रासंगिकता

- संरचनात्मक परिवर्तनों, औद्योगिक नीति **और** आर्थिक लचीलेपन **को समझने में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लागू**।

दैनिक समाचार विश्लेषण

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- **नीति निर्माताओं के लिए:**
  - नवाचार आधारित आर्थिक विकास **को बढ़ावा देने और स्टार्ट-अप, उद्यमिता और डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने** वाली नीतियों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **शिक्षा के लिए:**
  - इतिहास, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी **के चौराहे पर अंतःविषय अनुसंधान को आगे बढ़ाता** है।
  - विकास अर्थशास्त्र, औद्योगिक नीति और विकास अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक ढांचे **प्रदान करता है**।
- **व्यापार और उद्योग के लिए:**
  - प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए **अनुसंधान एवं विकास निवेश** और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों **को अपनाने** के महत्व को रेखांकित किया

आगे की चुनौतियाँ

- नवाचार और रचनात्मक विनाश पर सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को **व्यावहारिक नीति कार्यान्वयन में अनुवादित करना**, विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में।
- औद्योगिक परिवर्तनों के दौरान सामाजिक **और रोजगार स्थिरता** के साथ नवाचार-संचालित विकास को संतुलित करना।
- सभी क्षेत्रों और आय समूहों **में प्रौद्योगिकी और नवाचार लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना**।
- बौद्धिक संपदा और घरेलू औद्योगिक प्राथमिकताओं का प्रबंधन करते हुए **वैश्विक सहयोग को** बढ़ावा देना।

निष्कर्ष :

मोकिर, एघियोन और होविट को दिया गया 2025 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार **आर्थिक विकास को बनाए रखने में नवाचार की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है**। उनका शोध ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के साथ जोड़ता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे समाजों **को ठहराव से बचने के लिए निरंतर तकनीकी नवाचार और रचनात्मक विनाश** को बढ़ावा देना चाहिए। यह पुरस्कार 21**वीं सदी में लचीली**, **विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाएं बनाने में नीति**, संस्थागत समर्थन और उद्यमिता के महत्व को रेखांकित करता है।

UPSC PRELIMS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: एघियन और हॉविट द्वारा उजागर रचनात्मक विनाश की अवधारणा को संदर्भित करता है:

a) पुराने उत्पादों को नए उत्पादों से बदलना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

b) औद्योगीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश

c) मंदी के दौरान वित्तीय प्रणालियों का टूटना

d) सरकारी विनियमन द्वारा एकाधिकार का पतन

उत्तर : a)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

प्रश्न: भारत के औद्योगिक और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रचनात्मक विनाश की प्रासंगिकता की जांच करें। सरकार की नीति रोजगार और सामाजिक स्थिरता के साथ नवाचार को कैसे संतुलित कर सकती है? **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

दैनिक समाचार विश्लेषण

Estimating India's potential growth rate

C. Rangarajan

is Chairman, Madras School of Economics, and former Governor, Reserve Bank of India

D.K. Srivastava

is Honorary Professor, Madras School of Economics, and Member, Advisory Council to the Sixteenth Finance Commission

Several authors, including us, have argued that a growth rate of 6.5% appears to be the potential growth rate of India as of now. But the first quarter growth rate of 2025-26 is estimated at 7.8%. Does this alter our perception about the potential growth rate?

The first quarter real GDP growth in the post-COVID-19 years, from 2022-23 to 2024-25, has averaged 9.9% as compared to corresponding average levels of the second, third and fourth quarters of 7.0%, 6.9% and 7.5%. Thus, a 7.8% real GDP growth in the first quarter of 2025-26 is below the average for the first quarter of the previous three years. The annual real GDP growth rates for 2022-23 to 2024-25 were at 7.6%, 9.2% and 6.5%, respectively.

On the output side, real GVA growth in the first quarter of 2025-26 was 7.6%. This was also lower than the corresponding average GVA growth of 9.5% in the previous three years. The GVA growth in the first quarter of 2025-26 was largely based on improvements in the growth rates of manufacturing and the three important services sectors. It was mainly in manufacturing that the first quarter 2025-26 growth at 7.7% was higher than average first quarter growth for the previous three years at 5.8%.

Potential growth rate and ICOR

We may note that in the three important service sectors – namely trade, transport and others, financial, real estate and others, and public administration and others, growth rates in the first quarter of 2025-26 were quite high at 8.6%, 9.5% and 9.8%. But these were still lower than their corresponding averages in the previous three years at 12.9%, 11.3% and 13.1%, respectively. An increase in potential growth rate would require a sustained increase in growth in all these sectors. It is also important to note that the real gross fixed capital formation rate (GFCFR) in the first quarter was nearly the same in 2023-24, 2024-25 and 2025-26 at 34.5%, 34.6% and 34.6%, respectively. Thus, there is no structural break.

The estimation of 6.5% as potential growth rate in our article, "Potential growth stays at 6.5%" (*The Hindu-BusinessLine*, July 4, 2025) is based on the behaviour of GFCFR and Incremental Capital-Output Ratio (ICOR). While the GFCFR does not fluctuate too much, the ICOR is very volatile. The probable reason is that it is not estimated independently. It is derived from dividing the real GFCFR by real GDP growth rate. Thus, the fluctuations in growth get reflected in the ICOR. It is notable that the real GFCFR has been stable at 33.6%, 33.5%, and 33.7% of GDP during 2022-23, 2023-24 and 2024-25, respectively. Using an average ICOR on the GFCFR, the potential growth rate may be derived. With the GFCFR remaining at an average of 33.6% and an ICOR of 5.2, the potential growth rate remains at around 6.5%. For potential growth to rise above this level, it is important that the GFCFR improves tangibly above this average level for the previous three years or the ICOR falls below 5.2.

It may be noted that growth rates and the ICOR have been volatile in recent years because of the COVID-19 pandemic and subsequent adjustments. In estimating India's potential growth rate, one has to look at its performance over a much longer period. India's real GDP growth rate during 2011-12 to 2023-24 averaged 6.1%. In assessing a country's growth potential one may have to give greater weight to recent performance.

Positive and negative forces may balance themselves out, leaving a figure that is close to 6.5%

On public sector investment

The ICOR is a reflection of how efficiently capital is used. Technology and management ultimately determine the ICOR. One can be confident of sustained higher growth only if fixed capital formation rate goes up. A recent phenomenon in gross fixed capital formation is the bigger role played by government expenditure. In recent years, the share of the public sector in total real GFCF has increased from 21.6% in 2021-22 to 25.1% in 2023-24. Public sector investment is largely focused on infrastructure which has a high sectoral ICOR.

The surge in public sector investment was largely led by the central government. However, that momentum appears to be slowing down. Growth in the Centre's capital expenditure was at 39.4%, 24.4%, and 28.9% in 2021-22, 2022-23 and 2023-24, respectively. However, this growth fell to 10.8% in 2024-25.

In order to increase the potential growth rate above 6.5%, we will need to increase the GFCFR by about 2% points from the recent average GFCFR which is around 34%. This will call for an increase in the share of real investment of the private corporate sector in total GFCF which has fallen from 37% to 34.4%, during 2021-22 to 2023-24. This may be supplemented by a reduction in the ICOR.

Prospects of growth

Some of the influences that may affect the long-term potential growth on the positive side would include the impact of changing technology such as Artificial Intelligence (AI) and Gen AI. On the negative side, there would be the impact of a growing share of capital consumption as capital stock becomes older and new technologies call for a replacement of old capital at a faster rate. These forces may balance themselves out, leaving India's long term potential growth close to 6.5%.

The global trade environment also remains challenging for India. Given the tariff and supply chain uncertainties, much depends on the pace at which India is able to diversify its trade destinations and investment sources globally. After remaining positive for the previous four consecutive quarters, the contribution of net exports turned negative at (-)1.4% points in the first quarter of 2025-26. This trend is likely to continue. We may recognise that a potential growth rate of 6.5% is, in the present world environment, a reasonably high level, although for creating a higher growth of employment, we do need to push our potential growth further. For this, we need to get the private investment rate to move up. Policymakers need to address this issue at the aggregate and sectoral levels. They must understand what is holding back private investment and suggest appropriate remedies.

The views expressed are personal

GS. Paper 3- भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC Mains Practice Question: उच्च संभावित विकास को बनाए रखने में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की भूमिका पर चर्चा करें। एक स्थिर जीएफसीएफ जरूरी नहीं कि उच्च संभावित वृद्धि का संकेत क्यों न दे?(150 शब्द)

दैनिक समाचार विश्लेषण

संदर्भ:

मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष और आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन भारत की संभावित विकास दर का विश्लेषण करते हैं, जिसमें यह 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी वृद्धि सहित अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, लेखक का तर्क है कि दीर्घकालिक सतत विकास सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ), पूंजी उपयोग की दक्षता (आईसीओआर), निजी क्षेत्र के निवेश और संरचनात्मक कारकों पर निर्भर करता है। यह लेख आउटपुट-साइड प्रदर्शन और पूंजी दक्षता दोनों का मूल्यांकन करता है, जिसमें भारत के विकास पथ को आकार देने में सार्वजनिक और निजी निवेश की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिंदु

1. GDP और जीवीए प्रदर्शन

- पहली तिमाही जीडीपी 2025-26: 7.8% (पिछले तीन पोस्ट-कोविड वर्षों की 9.9% औसत Q1 वृद्धि से नीचे)।
- वास्तविक जीवीए वृद्धि Q1 2025-26: 7.6% (9.5% के पूर्व Q1 औसत से नीचे).
- क्षेत्रीय योगदान:
    - विनिर्माण Q1 की वृद्धि: 7.7% (पिछले तीन साल के Q1 औसत 5.8% से अधिक)।
    - सेवा क्षेत्र (व्यापार, परिवहन, वित्तीय और रियल एस्टेट, लोक प्रशासन): 8.6%, 9.5% और 9.8% की वृद्धि, 12-13% के ऐतिहासिक औसत से नीचे।

2. संभावित विकास और आईसीओआर

- अनुमानित संभावित विकास दर: ~6.5%।
- आधार: 2022-23 से 2024-25 तक स्थिर जीएफसीएफआर (~34%) और औसत आईसीओआर (~5.2)।
- निहितार्थ: उच्च संभावित विकास के लिए, या तो जीएफसीएफआर को बढ़ना चाहिए या आईसीओआर में गिरावट होनी चाहिए।

3. पूंजी निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

- कुल वास्तविक GFCF में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.6% (2021-22) से बढ़कर 25.1% (2023-24) हो गई, मुख्य रूप से उच्च ICOR वाले बुनियादी ढांचे में।
- केंद्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि 2021-22 में 39.4% से घटकर 2024-25 में 10.8% हो गई।
- निजी कॉर्पोरेट निवेश हिस्सेदारी 37% से गिरकर 34.4% हो गई, जो निजी क्षेत्र के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

4. संभावनाएं और बाधाएं

- सकारात्मक प्रभाव: एआई और जेन एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां, उत्पादकता लाभ।
- नकारात्मक प्रभाव: उम्र बढ़ने वाली पूंजी स्टॉक, तेजी से प्रतिस्थापन की जरूरतें, अस्थिर वैश्विक व्यापार, शुद्ध निर्यात योगदान नकारात्मक हो रहा है (Q1 2025-26 में -1.4%)।
- नीति फोकस: निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां।

दैनिक समाचार विश्लेषण

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
संभावित विकास दर अवधारणा	मुद्रास्फीति को ट्रिगर किए बिना प्राप्त करने योग्य दीर्घकालिक सतत विकास का प्रतिनिधित्व करता है।
जीएफसीएफ और आईसीओआर	पूंजी दक्षता और निवेश-संचालित विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मेट्रिक्स।
सार्वजनिक बनाम निजी निवेश	कारपोरेट क्षेत्र के निवेश बनाम सरकारी बुनियादी ढांचे पर खर्च की भूमिका पर प्रकाश डाला।
सेक्टोरल ग्रोथ पैटर्न	विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन संरचनात्मक ताकत और कमजोरियों को इंगित करता है।
वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी	एआई, जेन एआई और व्यापार विविधीकरण भारत की मध्यम से दीर्घकालिक विकास क्षमता को प्रभावित करते हैं।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक विकास

- अल्पकालिक जीडीपी में उतार-चढ़ाव (7.8% Q1 2025-26) दीर्घकालिक क्षमता को नहीं बदलते हैं, जो संरचनात्मक पूंजी दक्षता और निरंतर निवेश दरों पर निर्भर करता है।

2. पूंजी निर्माण और आईसीओआर

- GFCFR में स्थिरता का तात्पर्य कोई संरचनात्मक विराम नहीं है, जबकि ICOR अस्थिरता चक्रीय विकास विविधताओं को दर्शाती है।
- बढ़ती संभावित वृद्धि के लिए उच्च जीएफसीएफआर और कम आईसीओआर की आवश्यकता होती है, जिसे कुशल सार्वजनिक-निजी निवेश रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

3. निजी क्षेत्र का पुनरोद्धार

- संभावित वृद्धि को 6.5% से ऊपर बढ़ाने के लिए निजी कॉर्पोरेट निवेश महत्वपूर्ण है।
- निजी निवेश को अनलॉक करने के लिए संरचनात्मक सुधार, ऋण उपलब्धता और नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

4. तकनीकी और वैश्विक विचार

- एआई और जेन एआई उत्पादकता और आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, आंशिक रूप से पुरानी पूंजी और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को दूर कर सकते हैं।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और शुद्ध निर्यात संकुचन विकास प्राप्ति में बाधाएं हैं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- **नीति निर्माताओं के लिए:**
  - जीएफसीएफ को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, और प्रौद्योगिकी अपनाने और दक्षता में सुधार के माध्यम से आईसीओआर को कम करना।
  - विनिर्माण और सेवाओं के विकास को बनाए रखने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को दूर करना।
- अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के लिए:
  - जीएफसीएफआर और आईसीओआर का उपयोग करके संभावित विकास अनुमान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  - नीति विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक रुझानों और क्षेत्रीय योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- व्यापार और उद्योग के लिए:
  - बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में अवसरों का संकेत देता है।
  - राष् ट्रीय विकास को गति देने के लिए कारपोरेट निवेश और उत् पादकता बढ़ाने की आवश् यकता पर जोर दिया।

आगे की चुनौतियाँ

- धीमे सार्वजनिक निवेश को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ के हिस्से को पुनर्जीवित करना।
- तकनीकी अपनाने, बेहतर प्रबंधन और क्षेत्रीय दक्षता के माध्यम से ICOR को कम करना।
- वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के साथ घरेलू निवेश की जरूरतों को संतुलित करना।
- पूंजी प्रतिस्थापन चक्रों का प्रबंधन करते हुए एआई और जेन एआई नवाचारों को एकीकृत करना।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करना जो रोजगार सृजन में उच्च क्षमता का अनुवाद करता है।

निष्कर्ष :

C. रंगराजन के अनुसार, 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% जैसे उच्च अल्पकालिक जीडीपी आंकड़ों के बावजूद, भारत की दीर्घकालिक संभावित विकास दर लगभग 6.5% बनी हुई है। इस क्षमता को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए उच्च जीएफसीएफ, कुशल पूंजी उपयोग और अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो तकनीकी अपनाने और संरचनात्मक सुधारों द्वारा पूरक है। हालांकि अल्पकालिक प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक क्षमता और निवेश दक्षता अंततः भारत के सतत विकास पथ को निर्धारित करती है।

NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

सफलता बैच (Pre 2 Interview)

- DURATION : 1 YEAR
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)

ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

दैनिक समाचार विश्लेषण

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**